प्रेषक.

विनोद फोनिया सचिव

• उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में.

समस्त जिलाधिकारी. उत्तराखण्ड।

लघु सिंचाई विमाग

देहरादून : दिनांक: 24 अगस्त, 2009

विषय: वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए जिला योजना के अन्तर्गत

आयोजनागत मदों में धनावंटन।

महोदय,

क्पवा उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 994 / 11-2009-03 (05) / 2009, दिनांक 18:06:2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकें द्वारा लघु सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2009-10 में जिला योजना के अन्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से बार माह हेतु प्राविधानित बजट की धनराशि के सापेक्ष रूपये 233:48 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्मत की गई थी।

वितीय वर्ष 2009—10 के प्रथम चार माह हेतु लेखानुदान के माध्यम सं हुये-बजट प्राविधान एवं सम्पूर्ण वितीय वर्ष हेतु स्वीकृत बजट प्राविधान में भिन्नता होने के कारण पूर्व में शासनादेश दिनांक 18.06.2009 के द्वारा निर्गत वितीय स्वीकृति को संशोधित करते हुए वितीय वर्ष 2009—10 हेतु संलग्न विवरणानुसार कुल रूपया 283.62 लाख (रूपया दो करोड तिरसठ लाख बावन हजार माज) की वितीय स्वीकृति निम्न शर्ता एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग शासनादेश सं० 338 / 11–2004 / 2005 दिनांक 31.03.2005 एवं शासनादेश सं०–1454 / 11–2007—14(05) / 2005, दिनांक 06.12.2007 में निहित प्राविधानानुसार

किया जायेगा।

- 2— स्वीकृत घनराशि का व्यय केयल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह घनराशि की स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। घनराशि के अन्यत्र विघलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरवायी होंगे। जिला योजना से सम्बन्धित कार्यो पर व्यय जिला अनुअवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।
- 3— स्वीकृत धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या 875 / 1 |- 2009 14(05) / 2005 दिनाक 01.06.2009 एवं उत्तरखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेन्ट) नियमावली 2008 में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत किया आयेगा।
- 4— उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययिता के विषय में समय—समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
- 5— स्वीकृत धनराशि का खण्डवार/फॉट सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की जायेगी, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिला योजना की फॉट जिला अनुश्रदण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय के आधार

पर की जाय तथा अनुमोदित परिव्यय से अधिक व्यथ कदापि न किया जाय।

- 6- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड एवं वित्त विमाग को उपलब्ध कराया जाय।
- 7— कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 8— त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उक्त त्रैम सं में पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वालू वित्तीय वर्ष 2009—10 के आय व्ययक की अनुदान सँ0—20 के अन्तर्गत संलग्नक के कालम—2 में उल्लिखित उपलेखा शीर्षकों के जन्तर्गत सुसगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विमाग के अ०शा० पत्र सं० 195(P)/वित्त-4 /2009 दिनांक : अगस्त 20, 2009 से प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा एहें हैं।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीय, (विनीद फोनिया) सचिव।

संख्या 1311 / 11-2009-03(05) / 2008,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- 3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
- 4- स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
- 6- अपर सचिव, वित्त, बजट, अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7 अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्ता पाँडी / हल्द्वानी ।
- 8- समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिवाई उत्तराखण्ड।
- समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
 जिला पंचायत उत्तराखण्ड।
- अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 11- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 12 निवेशक, सब्द्रीय सूचना केन्द्र, संविवालय परिसर, देहरादून।
- 13- वित्त विभाग (वित्त अनुभाग-4), उत्तराखण्ड शासन।
- 14- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 15- गार्ड फाईल। संलग्न : यथोक्त।

(एस०एस० टोलिया) अन् सचिव